राजस्थान राज्य

बनाम

डा.राजकुमार अग्रवाल और अन्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 1222)

17 अगस्त, 2012

[अफतब आलम और रंजना प्रकाश देसाई, जे. जे.]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग-समझाया गया।

धारा 482 - उच्च न्यायालय ने सरकार में एक सर्जन, प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। अवैध संतुष्टि स्वीकार करने के लिए अस्पताल-आयोजितःतत्काल मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप और एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं प्राथमिकीते हैं और कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा-यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है जहां एफ. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है-उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि इसमें निहित संपूर्ण शक्ति-482 का प्रयोग सावधानीपूर्वक और बहुत संयम से किया जाना चाहिए-परिस्थितियों में, आरोपित निर्णय और आदेश को दरकिनार प्राथमिकी दिया जाता है।

अभ्यास और प्रक्रियाःआपराधिक कार्यवाही में शपथ पत्र-आयोजितःपी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों जैसे गंभीर अपराधों में जांच के चरण में या अदालती कार्यवाही के दौरान गवाहों द्वारा हलफनामा दायर करने की प्रथा को प्रोत्साहित करना

अदालतों के लिए जोखिम भरा होगा क्योंकि एक प्रभावशाली आरोपी के लिए इस तरह के हलफनामे प्राप्त करना और उनका उपयोग एफ. आई. आर.-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को रद्द करने के लिए करना आसान है।

राज्य सरकार के अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य चिकित्सा) के रूप में काम कर रहे प्रतिवादी संख्या 1 को एक 'एस. एल.' की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लगाए गए जाल में Rs.1500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। 1 ने अपनी चाची के ऑपरेशन के लिए उससे 5,000/- रुपये की मांग की थी, जिसका ऑपरेशन प्रतिवादी नं। 1 और अस्पताल से उसकी छुट्टी का इंतजार कर रहा था। प्रतिवादी 1 के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (1) (डी) (2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सक्षम प्राधिकारी से उसके अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त की गई थी।प्रत्यर्थी एफ ने उक्त एफ. आई. आर. को रद्द प्राथमिकीने के लिए धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत एक याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी।

राज्य की अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1.अभियोजन पक्ष के अनुसार, जाल सफल रहा। ट्रैप के उद्देश्य से रासायनिक रूप से उपचारित मुद्रा नोट उत्तरदाता 1 के साथ पाए गए और उनके हाथ का परीक्षण सकारात्मक पाया गया।रोगी और उसके पति ने अपने बयानों में दर्ज किया है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता का आंशिक रूप से समर्थन किया गया है।यह भी ध्यान दें योग्य है कि जब शिकायत दर्ज की गई थी, तब भी रोगी अस्पताल में था।इसके अलावा, पुलिस का दावा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता और प्रतिवादी 1 के बीच बातचीत को टेप किया है और कहा जाता है कि प्रतिवादी ने जांच के उद्देश्य से अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया है। जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए

साक्ष्य कितने विश्वसनीय हैं, यह तभी तय किया जा सकता है जब मुकदमे के दौरान साक्ष्य का परीक्षण प्रतिपरीक्षा द्वारा किया जाए। लेकिन, प्राथमिकी आर. की सामग्री और जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है जहाँ प्राथमिकी आर. को रद्द किया जा सके।यह नहीं कहा जा सकता है कि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं प्राथमिकीते हैं और कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।[पैरा 8-9) [326-ई-एफ, एच; 327-ए-डी; 328-सी)

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1990 (3) पूरक एस. सी. आर. 259 = 1992 सप(1) 335 - पर भरोसा किया।

1.2 जैसा कि इस अदालत द्वारा शिजी @पप्पु * मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति की प्रचुरता अपने आप में उच्च न्यायालय के लिए अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना अनिवार्य बनाती है।शक्ति की व्यापकता और प्रकृति स्वयं यह माँग करती है कि इसका प्रयोग कम किया जाए और केवल उन मामलों में जहां उच्च न्यायालय, कारणों को दर्ज करने के लिए, स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है कि अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि संहिता की धारा 482 के तहत उसमें निहित संपूर्ण शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और बहुत संयम से किया जाना चाहिए। परिस्थितियों में, विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 9 और 11] [327-एच; 328-ए-सी; 328-एफ] डी

*शिजी उपनाम पप्पु और अन्य. वी.राधिका और अन्र 2011 (13) एससीआर

135 = (2011) 10 एससीसी 705-संदर्भित

2. प्रतिवादी 1 रोगी, उसके पति और एक अन्य रोगी द्वारा दायर तीन हलफनामों पर भरोसा कर रहा है। इन हलफनामों के आधार पर शिकायत को रद्द करना मुश्किल है। पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों जैसे गंभीर अपराधों में जांच के चरण में या अदालती कार्यवाही के दौरान गवाहों द्वारा हलफनामा दायर करने की प्रथा को प्रोत्साहित करना अदालतों के लिए जोखिम भरा होगा क्योंकि एक प्रभावशाली आरोपी के लिए इस तरह के हलफनामे प्राप्त करना और उनका उपयोग एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए करना आसान है। 327-ई-एफ]

मामला कानून संदर्भः

1990 (3) पूरक पैरा 6 2010 (11) को संदर्भित एस. सी. आर. 259 लागू नहीं होने वाला एस. सी. आर. 788 पैरा 72011 (13) एस. सी. आर. 135 विशिष्ट पैरा 7

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः2012 की आपराधिक अपील संख्या 1222।

एस. बी. आपराधिक विविध मामले की याचिका सं. 307/2009 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.09.2009 के निर्णय और आदेश से

अपीलकर्ता की ओर से डॉ. मनीष सिंघवी, ए. एएजी, प्रगति नीखरा।

प्रतिवादीओं की ओर से पल्लव शिशोदिया, मुकुल कुमार।

न्यायालय का निर्णय (श्रीमति) रंजना प्रकाश देसाई, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अवकाश अनुदत्त गई।

2. राजस्थान राज्य द्वारा विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई यह अपील, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सीआरआई में दिए गए 10/9/2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। विविध।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता")

की खंड 482 के तहत प्रतिवादी 1-डॉ. राजकुमार अग्रवाल द्वारा 2009 की याचिका दायर की गई।विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी 1 के खिलाफ सोहन लाल (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी 1 ने श्रीमती का संचालन करने के लिए अवैध रूप से 5,000/- रुपये की मांग की थी। सीता देवी, जिन्हें वे अपनी चाची मानते थे।इस अदालत के समक्ष सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत को रद्द करने के लिए संहिता की खंड 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग इस मामले के तथ्यों में आवश्यक था।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैंःप्रतिवादी 1 जूनियर स्पेशलिस्ट (सर्जरी), सरकारी अस्पताल, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान के रूप में काम कर रहा था।11/12/2007 पर, शिकायतकर्ता ने पुलिस स्टेशन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (संक्षेप में, "ACB") चौकी, श्रीगंगानगर को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि 7/12/2007 पर, प्रतिवादी 1 ने अपनी चाची-श्रीमती के गर्भाशय का ऑपरेशन किया। सीता देवी डब्ल्यू/ओ।सूरतगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में नवरंगलाल। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने ऑपरेशन और बेहतर इलाज के लिए रिश्वत के रूप में 5,000/- रुपये की मांग की।शिकायतकर्ता ने ऑपरेशन के समय 2,500/- रुपये की राशि दी।शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी चाची अभी भी अस्पताल में थी और प्रतिवादी 1,500/- रुपये की शेष राशि की मांग कर रहा था।शिकायतकर्ता के अनुसार, वह पैसे नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे आशंका थी कि यदि प्रतिवादी राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह उसकी चाची को नुकसान पहुंचा सकता है।

4. याचिकाकर्ता का मामला है कि उसी दिन सुबह लगभग 11.00 बजे, एक छोटे से टेप-रिकॉर्डर में एक खाली कैसेट "ए" डाला गया और ए. सी. बी. कार्यालय में शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया।शिकायतकर्ता को इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया

गया।श्री जगदीश राय, Ct.No.179 को शिकायतकर्ता के साथ रिश्वत की मांग के सत्यापन के लिए सूरतगढ़ भेजा गया था।शाम 5 बजे शिकायतकर्ता और श्री जगदीश राय दोनों ए. सी. बी. कार्यालय लौट आए।टेप-रिकॉर्डर चलाया गया और मांग की पुष्टि की गई।इसका ज्ञापन तैयार किया गया और कैसेट को सील कर दिया गया और लेबल लगा दिया गया।यह अपीलकर्ता का मामला है कि जाल की तैयारी की गई थी।दो स्वतंत्र गवाहों अर्थात् श्री दर्शन सिंह, सहायक अभियंता और श्री कृपाल सिंह, सहायक परियोजना (समन्वय) कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, श्रीगंगानगर को शिकायतकर्ता से मिलवाया गया।शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत 1,500/- रुपये के मुद्रा नोट, जिन्हें अपीलकर्ता को सौंपा जाना था, पर फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगा हुआ था।आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया। टेप रिकॉर्डर में एक नया खाली कैसेट डाला गया और इसे शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया। 12/एफ 12/2007 को, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकायतकर्ता, दो स्वतंत्र गवाहों और अन्य लोगों के साथ सूरतगढ़ के लिए रवाना हुए।शिकायतकर्ता को प्रतिवादी से संपर्क करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया था 1 जाल पक्ष वहां इंतजार कर रहा था।शिकायतकर्ता प्रतिवादी 1 के आवास से बाहर आया और जी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निश्चित संकेत दिया।छापा मारने वाला पक्ष स्वतंत्र गवाहों के साथ शिकायतकर्ता के पास गया, जिसने कहा कि प्रतिवादी 1 ने शिकायतकर्ता के रिश्वत के पैसे को अपनी मेज के दराज में रखा था।टेप रिकॉर्डर पर प्रतिवादी 1 और शिकायतकर्ता की बातचीत सुनी गई।इसके बाद, छापा मारने वाला पक्ष, दो स्वतंत्र गवाह और शिकायतकर्ता प्रतिवादी 1 के घर के अंदर चले गए।पूछताछ किए जाने पर, प्रतिवादी 1 ने कहा कि उसने पैसे को अपनी मेज के दराज में रखा था। पैसा बरामद किया गया और प्रतिवादी 1 का हाथ धोया गया जो गुलाबी हो गया। आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, प्रतिवादी 1 के खिलाफ पुलिस स्टेशन, ए. सी. बी. चौकी, श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप

में, "पी. सी. अधिनियम") की धारा 7 और 13 (1) (डी) (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन के लिए मंजूरी 23/6 2009.5 पर प्रतिस्पर्धा ए-टी प्राधिकरण से प्राप्त की गई थी।जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रतिवादी 1 ने उक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए संहिता की खंड 482 के तहत याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उक्त एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया है। राजस्थान राज्य हमारे समक्ष अपील कर रहा है।

6. श्री मनीष सिंघवी, अड्डी।अपीलकर्ता के महाधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एफ. एल. आर. को रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है। वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट मामले में इस अदालत के फैसले के अनुपात की गलत व्याख्या की।(1) 335.वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई प्राथमिकी और अन्य सामग्री प्रथमदृष्टया प्रतिवादी 1 के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाती है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी 1 के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पल्लव शीशोदिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने शिकायत को सही ढंग से रद्द कर दिया है।उन्होंने बताया कि श्रीमती. सीता देवी का शिकायतकर्ता से कोई संबंध नहीं था।इसलिए, शिकायतकर्ता का मामला कि वह श्रीमती के गर्भाशय ऑपरेशन के संबंध में प्रतिवादी 1 के पास गया। सीता देवी और प्रत्यर्थी 1 द्वारा उनसे मांगी गई राशि स्वाभाविक रूप से असंभव है। वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता अस्पताल के पास एक केमिस्ट की दुकान का मालिक है जिसमें प्रतिवादी 1 काम कर रहा है।शिकायतकर्ता के पास केमिस्ट की दुकान चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है।शिकायतकर्ता द्वारा की गई अवैधताओं के बारे में प्रतिवादी 1 को पता था और इसलिए शिकायतकर्ता ने इस मामले में प्रतिवादी 1 को गलत तरीके से फंसाया है। वकील ने बताया कि संहिता की खंड 161 के तहत दर्ज

अपने बयानों में, श्रीमती. सीता देवी के साथ-साथ उनके पति ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से किसी पैसे की मांग की थी।वास्तव में, श्रीमती सीता देवी और उनके पति ने शपथ पत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी 1 ने कभी भी धन और श्रीमती के प्रति उनके व्यवहार के लिए नहीं कहा। सीता देवी अच्छी थीं और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। उनके निवेदन के समर्थन में, वकील ने वी. पी. श्रीवास्तव अन्य इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया। (2010) 10 एस. सी. सी. 361 और शिजी उपनाम पप्पु और अन्य। वी. राधिका और अन्र। (2011) 10 एससीसी 705।वकील ने प्रस्तुत किया कि श्रीमती। सीता देवी और उनके पति ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन पक्ष एक लंगड़ा अभियोजन बन गया है और सभी संभावनाओं में मामला निष्फल हो जाएगा।इसलिए, उच्च न्यायालय ने शिकायत को सही ढंग से रद्द कर दिया है क्योंकि यदि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, भले ही यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायत एक प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपराध वर्ष 2007 का है; कि प्रतिवादी 1 सेवानिवृत्ति के कगार पर है और उसने 2007 से आज तक जांच की पीड़ा और आपराधिक मुकदमे की संभावना का सामना किया है, यह अदालत मामले पर एक दयालु दृष्टिकोण ले सकती है।वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले के तथ्यों में, यदि उच्च न्यायाधीशालय के आदेश की पुष्टि हो जाती है तो न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा।

8. हम श्री शीशोदिया की दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं।यह सच है कि शिकायतकर्ता का श्रीमती से कोई संबंध नहीं है। सीता देवी लेकिन प्रथमदृष्टया यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि शिकायतकर्ता को

प्रतिवादी 1 के खिलाफ कोई शिकायत है क्योंकि प्रतिवादी 1 को अपनी केमिस्ट दुकान के संबंध में कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी थी।चूंकि श्री शीशोदिया ने श्रीमती के बयानों का उल्लेख किया है। सीता देवी और नवरंग लाल को संहिता की खंड 161 के तहत दर्ज किया गया है, हमने उनका अध्ययन किया है।इन बयानों में, श्रीमती. सीता देवी और नवरंग लाल ने कहा है कि शिकायतकर्ता श्रीमती का इलाज कर रही थी। सीता देवी उनकी चाची थीं और उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था।नवरंग लाल ने कहा है कि अपने काम के कारण "उन्हें सूरतगढ़ छोड़ना पड़ा और इसलिए, शिकायतकर्ता ने श्रीमती को भर्ती कराया। अस्पताल में सीता देवी।जहाँ तक प्रत्यर्थी 1 द्वारा की गई धन की कथित माँग का संबंध है, उन्होंने कहा है कि प्रत्यर्थी 1 ने उनसे कोई धन की माँग नहीं की थी और उन्हें पता नहीं था कि प्रत्यर्थी 1 ने शिकायतकर्ता से कोई धन की माँग की थी या नहीं।इस प्रकार, ये बयान शिकायतकर्ता के मामले का समर्थन करते हैं कि वह श्रीमती का इलाज कर रहा था। सीता देवी उनकी चाची के रूप में; कि उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था और उन्होंने प्रतिवादी 1 का इलाज किया था।प्रत्यर्थी 1 तीन शपथपत्रों पर भरोसा कर रहा है।श्रीमती द्वारा शपथ पत्र दाखिल किए गए हैं। सीता देवी, नवरंग लाल और एक अन्य मरीज जिसका नाम देवचरण भगत है।आश्चर्य की बात है कि इन हलफनामों में, श्रीमती. सीता देवी और नवरंग लाल ने पूरी तरह से विपरीत संस्करण दिया है।उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी 1 के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है।प्रतिवादी 1 के एक अन्य रोगी देवरन भगत ने अपने शपथ पत्र में प्रतिवादी 1 को एक प्रमाण पत्र दिया है कि वह एक विशेषज्ञ डॉक्टर है और उसने कभी भी इलाज के लिए उससे कोई पैसा नहीं लिया था। इस स्तर पर, हम इन हलफनामों पर कोई अंतिम राय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमें इन हलफनामों के आधार पर शिकायत को रद्द करना मुश्किल लगता है।जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, श्रीमती। सीता देवी और उनके पति ने संहिता की खंड

161 के तहत दर्ज अपने बयानों में शिकायतकर्ता का आंशिक रूप से समर्थन किया है। इन बयानों के अलावा अपीलकर्ता के खिलाफ एक और प्रथमदृष्टया निर्णायक परिस्थिति है।पुलिस का दावा है कि उन्होंने प्रतिवादी 1 और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत को टेप किया है।हमने इस टेप में रिकॉर्ड की गई बातचीत की प्रतिलिपि पढ़ी है।हमारे लिए उच्च न्यायालय से सहमत होना संभव नहीं है कि प्रतिलेखन प्राथमिकी की पुष्टि नहीं करता है। प्रथमदृष्टया, हम महसूस करते हैं कि यदि इसे अन्य तथ्यों की पृष्ठभूमि में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि यह श्रीमती के संचालन से संबंधित है। सीता देवी और मांग उक्त कार्रवाई से संबंधित है।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, जाल सफल रहा। फिनोल्फथेलिन पाउडर से सना हुआ पैसा उत्तरदाता 1 के साथ पाया गया। प्रतिवादी 1 से बरामद नोटों का मिलान शिकायतकर्ता ए द्वारा जाल लगाने के उद्देश्य से पुलिस को दिए गए नोटों से किया गया और प्रतिवादी 1 का हाथ धोना गुलाबी हो गया। यह भी ध्यान दें योग्य है कि जब शिकायत दर्ज की गई थी, तो श्रीमती. सीता देवी अभी भी अस्पताल में थीं, शायद इसलिए कि पैसे सौंपने के बाद उन्हें छुट्टी दी जानी थी, और वास्तव में, उनका डिस्चार्ज कार्ड प्रतिवादी 1 की मेज पर पाया गया था। अपीलकर्ता का यह भी मामला है कि प्रतिवादी 1 ने जाँच के उद्देश्य से अपनी आवाज़ का नमूना देने से इनकार कर दिया।जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य कितने विश्वसनीय हैं, यह केवल तभी तय किया जा सकता है जब मुकदमे के दौरान साक्ष्य का परीक्षण प्रतिपरीक्षा द्वारा किया जाता है।लेकिन, हमारी राय में, प्राथमिकी आर. की सामग्री और जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है जिसमें प्राथमिकी आर. को रद्द किया जा सके।यदि हम भजन लाल में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में तत्काल एफ. आई. आर. की जांच प्राथमिकीते हैं तो उच्च न्यायालय से सहमत होना संभव नहीं है कि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप और उसी के समर्थन में एकत्र किए गए

साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं प्राथमिकीते हैं।

9. अभी भी एक और बहुत ही ठोस कारण है कि हम तत्काल प्राथमिकी को रद्द करने में असमर्थ हैं। पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों जैसे गंभीर अपराधों में जांच के चरण में या अदालती कार्यवाही के दौरान गवाहों द्वारा हलफनामा दायर करने की प्रथा को प्रोत्साहित करना जोखिम भरा है। यदि इस अदालत द्वारा इस तरह की प्रथा को मंजूरी दी जाती है, तो किसी भी प्रभावशाली आरोपी के लिए जांच के दौरान या अदालती कार्यवाही के दौरान गवाहों के हलफनामे प्राप्त करना और प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द करना आसान होगा।इस तरह की प्रथा गंभीर मामलों के निराशाजनक अभियोजन का कारण बनेगी।इसलिए हम इस तरह के हलफनामों पर भरोसा करने से सावधान हैं।जहाँ तक श्री शीशोदिया द्वारा वी. पी. श्रीवास्तव में उद्धृत निर्णय का संबंध है, यह विशुद्ध रूप से तथ्यों पर आधारित है और इस मामले में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।शिजी @पप्पु भी उत्तरदाता की मदद नहीं करता है।उस मामले में एक नागरिक विवाद शामिल था।पक्षों ने अपने दीवानी विवाद को सुलझा लिया था और इसलिए, शिकायतकर्ता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था।यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि शिजी @पप्पु मामले में, इस न्यायालय ने माना कि संहिता की खंड 482 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित था।हालाँकि, इस अदालत ने कहा कि संहिता की खंड 482 के तहत शक्ति की प्रचुरता अपने आप में उच्च न्यायालय के लिए अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना अनिवार्य बनाती है। शक्ति की व्यापकता और प्रकृति स्वयं यह माँग करती है कि इसका प्रयोग कम हो और केवल उन मामलों में जहां उच्च न्यायालय का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।हम महसूस करते हैं कि तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि संहिता की खंड 482 के तहत उसमें निहित संपूर्ण शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और बहुत संयम

से किया जाना चाहिए।इस मामले के तथ्यों पर हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि प्रतिवादी 1 के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है और कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

10. श्री शीशोदिया ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 1 सेवानिवृत्ति के कगार पर है। उन्होंने 2007 से जांच की पीड़ा झेली है और इसलिए, यह अदालत मामले पर दयालुता से विचार कर सकती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार देखा जाता है। लोग, विशेष रूप से उच्च पद धारण करने वाले, अक्सर अवैध संतुष्टि स्वीकार करते देखे जाते हैं।ऐसे गंभीर मामलों में इस स्तर पर दया दिखाना गलत संकेत भेज सकता है।इसलिए हम श्री शीशोदिया के अनुरोध मान लेना करने में असमर्थ हैं।

11. इन परिस्थितियों में, हम विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं। हमारे लिए यह स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक नहीं है कि हमारे द्वारा की गई सभी टिप्पणियाँ प्रथमदृष्टया टिप्पणियां हैं और जिस न्यायालय को इस मामले से जोड़ा जा सकता है, वह गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार सख्ती से निपटेगा।

12. अपील का निपटारा पूर्व-वर्णित शर्तों में किया जाता है।

आर. पी. अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।